

वित्त वर्ष 2025-26 का बजट

**आयकर छूट सीमा 12 लाख होने से एक करोड़
और लोगों को नहीं देना होगा कर : सीताएमण**



बजट में शिक्षा: एआई पर बढ़ावा, पांच नए आईआईटी में बुनियादी ढांचे का विस्तार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। सरकार द्वारा 2025-26 के बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए की गई बड़ी घोषणाओं में पांच नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (आईआईटी) में 6,500 और छात्रों की शिक्षा के लिए बुनियादी ढांचे का विस्तार, मेडिकल की 10,000 नई सीट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को बढ़ावा देना शामिल है। केंद्रीय बजट 2025-26 में शिक्षा मंत्रालय को 1.28 लाख करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किया गया है, जो 2024-25 के संशोधित अनुमान 1.14 लाख करोड़ रुपए से अधिक है।

उच्च शिक्षा विभाग को जहां 50,067 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है, वहां स्कूली शिक्षा विभाग को 78,572 करोड़ रुपए मिले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार स्कूल और उच्च शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं की पुस्तकों का डिजिटल रूप उपलब्ध कराने के लिए 'भारतीय भाषा पुस्तक' योजना शुरू करेगी। उन्होंने घोषणा की कि सरकार पांच

दांचे की क्षमता का भी विस्तार किया जाएगा।

केंद्रीय बजट में आईआईटी को 11,349 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो चालू वित्त वर्ष के 10,467 करोड़ रुपए के संशोधित अनुमान से अधिक है। सीतारमण ने घोषणा की कि अगले पांच वर्षों में 75,000 सीट जोड़ने के लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अगले साल मेडिकल कॉलेज और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीट जोड़ी जाएंगी।

सरकार के पास नए विचार नहीं, वित्त मंत्री 1991, 2004 की तरह आर्थिक सुधार करना नहीं चाहती : चिंदंबरम

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



भरे शब्द थे। पूर्व वित्त मंत्री ने दावा किया कि सामाजिक कल्याण, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समुदायों के लिए आवंटन में कमी की गई है। उन्होंने यह आरोप भी लगाया कि बजट में देश के युवाओं

को भी धोखा दिया गया है। वरिष्ठ नेता पी विंदबरम के अनुसार, यह सरकार पुराने ढर्डे पर चलती रहेगी जिससे आगामी वित्त वर्ष में छह या 6.5 प्रतिशत की वृद्धि दर ही देखने को मिलेगी जो भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जरूरी आठ प्रतिशत की वृद्धि दर से बहुत कम है।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि वित्त मंत्री 1991 और 2004 की तरह आर्थिक सुधार करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि इस सरकार के पास नए विचारों का अभाव है और इसमें अपने दायरे से बाहर निकलने की दृष्टिपात्रता नहीं है।

वित्त वर्ष 2025-26 के रक्खा बजट के लिए 6.81 लाख करोड़ रुपए आवंटित

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भाषा। भारत ने

धरलू हिस्से का 25 प्रतिशत यानी 27,886 करोड़ रुपए धरलू निजी उद्योगों के माध्यम से खरीद के लिए प्रावधान किया गया है। अगले वित्त वर्ष में सशस्त्र बलों के लिए पूँजीगत परिव्यय 2024-25 के बजटीय अनुमान 1.72 लाख करोड़ रुपए से 4.65 प्रतिशत अधिक है। 2024-25 के लिए संशोधित पूँजीगत परिव्यय 1,59,500 करोड़ रुपए अनुमानित किया गया है। कुल पूँजीगत परिव्यय 1,92,387 करोड़ रुपए रखा गया है, जिसमें से 12,387

पकरणों की खरीद शामिल है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि कुल बजट 6.81 लाख करोड़ रुपए का है जो चालू वित्त वर्ष के विविध से 9.53 प्रतिशत विधिक है। इसने पूंजीगत व्यय के दौरे में कहा कि 1,48,722.80 करोड़ रुपए नए सैन्य उपकरणों की खरीद के लिए आधुनिकीकरण बजट पर वर्च करने की योजना है और शेष 1,277 करोड़ रुपए अनुसंधान विकास तथा ढाचागत विसंपत्तियों के निर्माण पर खर्च करोड़ रुपए रक्षा सेवाओं के लिए रखे गए हैं। वर्ष 2024-25 में पूंजी परिव्यय 1.72 लाख करोड़ रुपए था और संशोधित अनुसार के अनुसार यह राशि 1,59,500 करोड़ रुपए है, जो बताता है कि लगभग 13,500 करोड़ रुपए की राशि अभी तक खर्च नहीं की गई है। अगले वित्त वर्ष के लिए दैनिक कामकाज और वेतन संबंधी राजस्व व्यय 4,88,822 करोड़ रुपए आंका गया है, जिसमें पेशन के लिए 1,60,795 करोड़ रुपए शामिल हैं।

गोली के घाव पर मरहम पट्टी
वाला बजट है, आर्थिक संकट
का समाधान नहीं : कांग्रेस

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com



के लिए राहत दी गई है, लेकिन अर्थव्यवस्था पर इसका वास्तविक प्रभाव क्या होगा, यह देखना अभी बाकी है। उन्होंने यह भी कहा कि इस साल हाने वाले विद्यानसभा चुनाव के चलते बिहार के लिए कझ घोषणाएं की गई हैं, जबकि आप्रवासी प्रदेश की अनदेखी की गई है।

रमेश ने 'एक्स' पर पोस्टर किया, अर्थव्यवस्था इस समय स्थिर वास्तविक मजदूरी, सामूहिक उपभोग में उछाल की कमी, निर्जन निवेश की सुरक्षा दरें तथा जटिल और पेचीदा जी-एसटी प्रणाली रूप संकटों से घिरी हुई है। बजट में इन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ नहीं है। उन्होंने कहा, ऐसा लगता है कि बिहार को घोषणाओं का खजाना मिल गया है। यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं। कांग्रेस वे संगठन महासचिव केरी वेणुगोपाल ने पोस्ट किया, बजट भारत की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था को पटर्स पर लाने के लिए कुछ नहीं करेगा।

केंद्रीय बजट में बिहार के लिए कई घोषणाएं

विपक्ष ने चुनाव से जोड़ा तो राजग ने किया पलटवार

दक्षिण भारत राष्ट्रमत
dakshinbharat.com

नई दिल्ली/भारत। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्भता सीतासंभान की ओर से शनिवार पर पेश किए गए आम बजट में महाना बोर्ड की स्थापना, पश्चिमी कोसी नदी के लिए वित्तीय सहायता और आईआईटी पटना की काशना में विस्तार सहित कई अन्य घोषणाएं कर विहार को खास तरजों दी गई हैं।

कांग्रेस सहित विपक्षी नेताओं ने कहा कि बजट 2025 में आम लोगों और सभी गण के लिए कुछ भी नहीं है तथा सरकार इसे आगामी विहार विधानसभा चुनाव



BUDGET BOOSTER FOR BIHAR

को ध्यान में रखकर लाई है। हालांकि आम बजट पार्टी (भाजपा) और इसके सहयोगी दलों ने इस आपको खारिज किया। विहार में इस साल के अंत में वहाँ जनता दल (राजनाइट) के नेता नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) की सरकार है।

लोकसभा में आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने यह भी घोषणा की कि केंद्रीय वित्तीय की जलरौपों को पूरा करने के लिए राज्य के लिए ग्रीनफाईल्ड हवाई अड्डों के विस्तार की अलापा विपक्षी ने एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की भी स्थापित

करेगा। पटना हवाई अड्डे की क्षमता का विस्तार किया जाना भी प्रमुख घोषणाओं में शामिल है। विहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नदी नहर परियोजना के लिए राज्य के विकास के लिए ग्रीनफाईल्ड हवाई अड्डों के विस्तार की अलापा विपक्षी ने एक राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की भी स्थापित

घोषणा हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बजट की सराहना करते हुए कहा था “सकारात्मक” है और इससे राज्य के विकास में तेजी लाने में वटद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री ने रेस्ट्रो मोटो और केंद्रीय वित्तीय की वज्रांग के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य वित्तीय की गई तथा पहले की अपनी घोषणाओं को वह नया बताकर किर से पेश कर रही है।

(जद-यू) केंद्र में सत्तारुद भाजपा नीत राष्ट्रीय गठबंधन की प्रमुख घटक है। नीतीश ने एक बयान में कहा कि ‘मखाना बोर्ड’ की स्थापना के प्रत्यावर से मखाने की खेती का बढ़ावा मिलेगा, जिसके लिए राज्य दू-दू तक जाना होता है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में प्रत्यावर ग्रीनफाईल्ड हवाई अड्डे उड़ान संसंकेत सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, जिससे राज्य के विवाह की हालातिक, राजग की सहयोगी दल जद-यू और आम दू-दू प्रदेश से तेजी वेशांग पार्टी (विपक्ष) के स्पष्ट संदर्भ में ‘एस्ट्र’ पर कहा, यह स्वाभाविक है क्योंकि साल के अंत में वहाँ (बिहार) दूसरे स्वरूप यानी आरोप लगाया जाता है। उन्होंने यह भी कहा कि बजट में विवाह के लिए एक राष्ट्रीय खाद्य वित्तीय की गई घोषणाओं को वह नया बताकर किर से पेश कर रही है।

